www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 18 जुलाई 2019

दैनिक जागरण
धैर्य अनेक मानवीय गुणों की जननी है

# भारत की जीत

पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में बंदी भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला भारत को एक बड़ी राहत देने वाला है। यह न्यायालय बहुमत से इस नतीजे पर पहुंचा कि एक तो कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद मिलनी चाहिए और दूसरे, पाकिस्तान को उन्हें सुनाई गई सजा की समीक्षा करनी चाहिए। इस मामले में भारत का पक्ष सही था, यह इससे साबित होता है कि केवल एक को छोड़कर शेष सभी न्यायाधीश इस पर एकमत रहे कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के बारे में भारत सरकार को समय पर सूचना न देकर वियना संधि का उल्लंघन किया। यह उल्लेखनीय है कि बहुमत से दिए गए इस फैसले में चीन के भी जज शामिल थे। इस पर हैरानी नहीं कि जो एकलौते जज फैसले से सहमत नहीं हुए वह पाकिस्तान के थे। कुलभूषण जाधव पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला भारत की कूटनीतिक और साथ ही कानूनी जीत है। कुलभूषण को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जाया जाए या नहीं, इस हिचक को तोड़ते हुए मोदी सरकार ने जिस कूटनीतिक साहस का परिचय दिया उसे और बल दिया वकील हरीश साल्वे की दलीलों ने। उनकी ही दलीलों को सुनकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को यह आदेश दिया था कि वह कुलभूषण को सुनाई गई फांसी की सजा पर अमल न करे। इसी आदेश के बाद पाकिस्तान कुलभूषण के परिजनों को अपने यहां आने की इजाजत देने के लिए बाध्य हुआ था, लेकिन इसके बावजूद अंतिम फैसला उसके पक्ष में नहीं आया।

इस पर आश्चर्य नहीं कि कुलभूषण की फांसी की सजा पर रोक के अंतरिम फैसले के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह यह प्रदर्शित किया था कि उसका पक्ष मजबूत है उसी तरह वह ताजा फैसले को भी अपने हक में बताने की कोशिश कर रहा है। स्पष्ट है कि वह सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार करने से कतरा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण को राजनयिक मदद उपलब्ध कराने के साथ ही यह रेखांकित किया है कि उन्हें दी गई फांसी की सजा की प्रभावी ढंग से समीक्षा करने के साथ ही उस पर नए सिरे से विचार किया जाए। निःसंदेह इसका अर्थ यही है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत के उस फैसले को संदेहास्पद पाया जिसके तहत कुलभूषण को आतंकवाद फैलाने का दोषी करार देकर फांसी की सजा सुना दी गई थी। यह सही है कि अतीत में कुछ समर्थ देशों ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसलों की अनदेखी की है, लेकिन पाकिस्तान की न तो इतनी हैसियत है और न ही हिम्मत कि वह ऐसा कुछ करने की सोच सके। पाकिस्तान आंतरिक संकट से दो-चार होने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहा है। इसी दबाव के चलते उसने आतंकी सरगना हाफिज सईद की एक और बार गिरफ्तारी का दिखावा किया है। भारत को इस दिखावे को उसकी चालबाजी के रूप में ही देखना होगा। इसी के साथ यह भी जतन करना होगा कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के चंगुल से कैसे छुड़ाया जाए? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले ने पाकिस्तान पर दबाव बनाने का जो अवसर दिया है उसका पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए।

# प्रभावी कदम जरूरी

विषम भूगोल वाले उत्तराखंड में मानव और गुलदारों के बीच छिड़ी जंग के बीच गुलदारों के व्यवहार में आ रहे बदलाव ने अब नई चुनौती खड़ी कर दी है। गांव-घरों के नजदीक गुलदार निर्भय होकर ऐसे घूम रहे, जैसे कि ये पालतू जानवर हों। विशेषकर राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में तो आलम यह है कि मौत रूपी गुलदार कब कहां आ धमके, कहा नहीं जा सकता। परिणामस्वरूप पहाड़ का आम जनमानस खौफ के साये तले रहने को मजबूर है। मानव और गुलदारों के बीच छिड़ा यह संघर्ष लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इसमें दोनों को जान देकर कीमत चुकानी पड़ रही है। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि राज्य में वन्यजीवों के हमलों में 80 फीसद घटनाएं गुलदारों की हैं। आसान शिकार की तलाश में आबादी के करीब धमक रहे गुलदारों के हमले की आए दिन होने वाली घटनाएं सुर्खियां बन रही हैं। कारणों की तह में जाएं तो इस स्थिति के लिए मानवजनित कारण अधिक हैं। जंगलों के अंधाधुंध कटान और शाकाहारी जानवरों के अवैध शिकार के कारण वनों में गुलदार का वासस्थल प्रभावित हुआ है। साथ ही जंगल में उसके लिए भोजन की कमी भी है। गुलदारों की संख्या में इजाफा होने की बातें भी सामने आ रही हैं। यही नहीं, पहाड़ के गांवों से निरंतर हो रहे पलायन के कारण गांव खाली हुए हैं तो खेत-खलिहान वीरान। जिन खेतों में कभी फसलें लहलहाती थीं, वहां आज झाड़ियों का साम्राज्य है। यही झाड़ियां गुलदारों के छिपने का अड्डा बन रही हैं। आसान शिकार की तलाश में ये मवेशियों के साथ ही लोगों पर लगातार हमले कर रहे हैं। अब तो समस्या और अधिक गहरा गई है। बावजूद इसके समाधान की दिशा में ठोस पहल नहीं हो पाई है। विशेषज्ञों की मानें तो गुलदारों को आदमखोर घोषित कर मार गिराना समस्या का समाधान नहीं है। इससे निबटने के लिए हमें बचाव के तौर-तरीके अपनाने होंगे। सतर्कता, निगरानी के साथ ही गांव-घरों और रास्तों को चारों तरफ कम से कम 20 मीटर तक स्थान खुला रखना होगा।

# परिवार की मुट्ठी में पार्टी

प्रदीप सिंह

**जो कांग्रेस का नया अध्यक्ष खोज रहे हैं और जो किनारे बैठकर सब कुछ देख रहे हैं उन्हें पता है कि अध्यक्ष कोई बने, पार्टी की बागडोर परिवार के पास ही रहेगी**

अवधेश राजपूत

शतरंज का खेल जानने वालों को पता है कि इस खेल में प्यादा राजा के अलावा सब कुछ बन सकता है, पर राजा, वजीर, ऊंट, घोड़ा किसी भी स्थिति में प्यादा नहीं बन सकते। शतरंज और राजनीति में काफी समानता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब वह प्यादा यानी आम कार्यकर्ता बनना चाहते हैं। इससे यही लगता है कि राहुल गांधी को राजनीति की बारीकियों की न तो पहले समझ थी और न अब है। जब साल 2004 में उन्हें प्यादा यानी कार्यकर्ता बनना था तो वह राजा बनना चाहते थे। अब जब राजा बन गए तो कह रहे हैं प्यादा बनना है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जवाबदेही से बचने के लिए उन्हें यही रास्ता नजर आ रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी परेशान है। अध्यक्ष पद के दावेदार सहमे हुए हैं। जिम्मेदारी और जवाबदेही के पद पर आसीन राहुल गांधी को समझना कठिन था। अब बिना किसी जिम्मेदारी और जवाबदेही वाले राहुल गांधी से कैसे निभाएं? प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी के इस्तीफे के कदम को साहसिक बताया है। यदि यही साहस है तो फिर रणछोड़ दास की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे में कहा कि देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। कठिनाई के समय मैदान छोड़ने वाले को साहसी कहने के लिए अंधभक्त होना जरूरी है। दरअसल राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी जिस हालत में पहुंच गई है वहां से उसे कैसे निकालें? उनके परिवार ने ही पार्टी को इस हालत में पहुंचाया है। नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के समय क्या हुआ, इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उस पर बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। कांग्रेस पार्टी रसातल की ओर जा रही है, इसके संकेत पार्टी को बार-बार मिल रहे थे। 1998 में पार्टी की बुरी हार और पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी ने एके एंटनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उसकी रिपोर्ट पर कार्यसमिति में घंटों बहस हुई, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। कमेटी 2014 (एंटनी) और 2016 (मोइली) में भी बनी। उसका क्या हुआ, किसी को पता नहीं। साल 2004 में गठबंधन के सहारे कांग्रेस सत्ता में आ गई और दस साल तक सत्ता में रही। इन दस वर्षों में सोनिया गांधी ने आजादी के आंदोलन की वारिस कांग्रेस को एक तरह के एनजीओ में बदल दिया।

कांग्रेस ने जिस राष्ट्रवाद को लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी उसे छोड़कर 'भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह-इंशाअल्लाह' वालों के साथ खड़ी हो गई। सोनिया की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद केंद्रीय मंत्रिमंडल से ज्यादा ताकतवर हो गई। प्रधानमंत्री बने बिना सोनिया गांधी सरकार चलाती रहीं। दस साल के संप्रग शासन में जो बुरा हुआ उसकी जिम्मेदारी मनमोहन सिंह की और जो अच्छा हुआ उसका श्रेय सोनिया गांधी या राहुल गांधी को। प्रेस कांफ्रेंस में अध्यादेश की प्रति फाड़ने वाले राहुल गांधी अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में दस साल तक मौन साधे रहे, लेकिन मुगालते का आलम देखिए कि उन्हें लगा कि 2019 आते-आते वह भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के सूरमा बन जाएंगे। वह बेईमानों के भ्रष्टाचार पर चुप्पी साधे रहे और ईमानदार छवि वाले पीएम को हर सभा में चोर बताते रहे। उन्हें तब भी समझ में नहीं आया जब उनसे ज्यादा अनुभव रखने वाले उन्हीं की पार्टी के नेता बताते रहे कि इस नारे को आम लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है।

गोस्वामी तुलसीदास लिख गए हैं। 'सचिव बैद गुरु तीन जौं प्रिय बोलहिं भय आस, राज धर्म तन तीनि कर होहिं बेगिहीं नास।' राहुल ने सचिव यानी सलाहकार ऐसे बनाए जो वही बोलते थे जो वह सुनना चाहते थे। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनसे कोई ऐसी बात कहना बंद कर दिया जो उन्हें पसंद न हो। सबका एक ही कहना था कि राहुल गांधी किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। गुरु उनके ऐसे जिन्होंने उन्हें कांग्रेस की विचारधारा छोड़, मंदिर-मंदिर घुमाया और टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ बैठाया। राहुल गांधी को आने वाले दुर्दिन की बार-बार दस्तक मिल रही थी। पहली दस्तक तब मिली जब 2015 में हेमंत बिस्व सरमा ने कांग्रेस छोड़ी। देश को पता चल गया कि राहुल गांधी की कार्यशैली में खामी है। सिर्फ राहुल गांधी को पता नहीं चला।

इंदिरा गांधी ने 1978 में कांग्रेस को अपने परिवार के वफादारों की पार्टी बनाने का जो सिलसिला शुरू किया था उसे राहुल गांधी ने अपनी बहन को महामंत्री बनाकर पूरा कर दिया। सोनिया राज में कांग्रेस में बड़े फैसले कार्यसमिति के बजाय दस जनपथ की डाइनिंग टेबल पर होने लगे। वहीं तय होता था कि कौन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का फैसला वहीं हुआ। उस समय तक पार्टी में न होने के बावजूद प्रियंका सबसे अधिक सक्रिय थीं। ताजा स्थिति यह है कि डाइनिंग टेबल के सभी सदस्य अब कार्यसमिति में आ गए हैं। प्रियंका ने कार्यसमिति की बैठक में कहा कि 'मेरा भाई अकेला लड़ रहा था।' आखिर उन्होंने अपने भाई से यह क्यों नहीं पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्या कमाल किया कि पूरी पार्टी होते हुए तुम्हें अकेले लड़ना पड़ा? भाई अकेला लड़ रहा था तो बहन कहां थीं? पूर्वी उत्तर प्रदेश तो उनके ही हवाले था। वह बाजी पलटने वाली बताई जा रही थीं, लेकिन पार्टी उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बचा सकीं। उन्होंने भाई के इस्तीफे को साहसिक कदम बताया, लेकिन खुद ऐसा साहसिक कदम उठाने से इन्कार किया।

राहुल गांधी के प्रति पार्टी में विश्वास का आलम यह है कि ज्यादातर लोग इस्तीफे को पहले ही दिन से नाटक मान रहे हैं। अब नए अध्यक्ष की तलाश हो रही है। जो लोग तलाश कर रहे हैं उन्हें किसने अधिकृत किया? पार्टी के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी ने ठीक ही कहा कि अच्छा होता कि राहुल इसकी व्यवस्था करते और कार्यसमिति उसे मंजूरी देती। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नया अध्यक्ष युवा पीढ़ी से होना चाहिए, पर इन दोनों नेताओं की आवाज नक्कारखाने में तूती की तरह है। जो नया अध्यक्ष खोज रहे हैं और जो किनारे बैठकर सब कुछ देख रहे हैं, उन सबको पता है कि अध्यक्ष कोई बने, पार्टी की बागडोर परिवार के पास ही होगी। जब सोनिया अध्यक्ष बनी थीं तो कम से कम तीन नेता-शरद पवार, जितेंद्र प्रसाद और राजेश पायलट ऐसे थे जिनमें चुनौती देने की हिम्मत थी। आज दूर-दूर तक ऐसा कोई नहीं है। कोई नहीं है जो राहुल गांधी से आंख मिलाकर बात कर सके।

सोनिया गांधी ने जो कांग्रेस बनाई उसकी एक ही विचारधारा है-परिवार के प्रति वफादारी। पार्टी के प्रति वफादारी वाले जो थोड़े से बचे हैं उनके पीछे 'सिद्ध प्रवृत्ति' वाले वफादार लगा दिए जाते हैं। कांग्रेस के पास दो ही विकल्प हैं-वह राहुल गांधी के नेतृत्व में ही गिरते-पड़ते चलती रहे या फिर राहुल अध्यक्ष पद से ही नहीं, पार्टी से भी हट जाएं, क्योंकि परिवार जब तक पार्टी में है, पार्टी की कमान उसी के हाथ में रहेगी। इसलिए किसी और के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

# बोलियों को भाषा बनाने की जिद

डॉ. करुणाशंकर उपाध्याय

**यदि हिंदी की किसी भी बोली को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो हिंदी बिखर जाएगी**

कुछ नेता भाषा को राजनीति के अखाड़े में खींच लाए हैं। वे भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदी की 38 बोलियों के समर्थक भी अपनी बोलियों के लिए ऐसा ही अभियान चला रहे हैं। इनमें अवधी, ब्रज, बुंदेली, मालवी, कुमाऊंनी, गढ़वाली, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, अंगिका, मगही, सरगुजिया, हालवी, बघेली आदि शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव भोजपुरी और राजस्थानी की ओर से है। भोजपुरी के समर्थक तो अवधी भाषी जनसंख्या एवं साहित्यकारों को भी अपने साथ दिखा रहे हैं। यह तय है कि यह भाषाई राजनीति केवल भोजपुरी और राजस्थानी को स्वतंत्र भाषा का दर्जा देने से खत्म नहीं होगी। जब तक सभी 38 बोलियों को भाषा का दर्जा नहीं मिलेगा वे तब तक संघर्षरत रहेंगी। इसके बाद मराठी, गुजराती, बांग्ला समेत दूसरी भाषाओं की बोलियां भी स्वतंत्र भाषा का दर्जा हासिल करने की मुहिम में जुटेंगी। ऐसी स्थिति में एक तरह की भाषिक अराजकता फैल सकती है। केवल वोट की राजनीति के लिए हिंद और हिंदी के स्वाभिमान पर चोट न की जाए। इस संदर्भ में महात्मा गांधी का कथन खासा उल्लेखनीय है, 'जो वृत्ति इतनी वर्जनशील और संकीर्ण है कि हर बोली को चिरस्थायी बनाना और विकसित करना चाहती हो वह राष्ट्र विरोधी और विश्व विरोधी है। मेरी विनम्र सम्मति में तमाम अविकसित और अलिखित बोलियों का बलिदान करके उन्हें हिंदी या हिंदुस्तानी की बड़ी धारा में मिला देना चाहिए। यह आत्महत्या नहीं, बल्कि देश हित के लिए दी गई कुर्बानी होगी।'

वास्तव में गांधी जी के इसी लक्ष्य को साकार करने का कार्य हमारे संविधान निर्माताओं ने किया। इस महादेश में आंतरिक एकता तथा संवाद का एकमात्र माध्यम बनकर हिंदी ने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। अंतरराष्ट्रीय भोजपुरी सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष डॉ. विद्यानिवास मिश्र ने लिखा था कि, 'जो बोलियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं वे यह भूल जाते हैं कि ये बोलियां एक दूसरे के लिए प्रेषणीय होकर बोलने वालों के लिए महत्व रखती हैं, परस्पर विभक्त हो जाने पर उनका कोई मोल न रह जाएगा।' साफ है कि यदि हिंदी का संयुक्त परिवार टूटता है तो देश भी कमजोर हो जाएगा। ऐसे में व्यापक राष्ट्रहित में हमें हिंदी को मजबूत बनाना चाहिए और बोलियों को भाषा बनाने का मोह छोड़ना चाहिए। आज निहित स्वार्थ के लिए जो लोग हिंदी को कमजोर करने का उपक्रम कर रहे हैं वे देश की भाषिक व्यवस्था के समक्ष संकट उत्पन्न कर रहे हैं। वे नहीं जानते हैं कि हिंदी के टूटने से देश की भाषिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाएगी और देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाला धागा टूट जाएगा। वस्तुतः जिसे हम राजभाषा हिंदी कहते हैं वह अनेक बोलियों का समुच्चय है। हिंदी की यही बोलियां उसकी प्राणधारा हैं जिनसे वह शक्तिशाली बनकर विश्व की सबसे बड़ी भाषा बनी है, लेकिन जो बोलियां विगत 1300 वर्षों से हिंदी का अभिन्न अंग रही हैं उन्हें कतिपय तत्व अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें एकजुट होकर हिंदी को टूटने से बचाना चाहिए अन्यथा देश की सांस्कृतिक-भाषिक व्यवस्था चरमरा जाएगी।

यहां विचारणीय है कि हिंदी और उसकी तमाम बोलियां अपभ्रंश के सात रूपों से विकसित हुई हैं और वे एक दूसरे से इतनी घुलमिल गई हैं कि परस्पर पूरकता का अद्भुत उदाहरण हैं। यह भी सच है कि हिंदी के भाग्य में सदैव संघर्ष लिखा है। वह संतों, भक्तों से शक्ति प्राप्त करके लोक शक्ति के सहारे विकसित हुई है। आज विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक होने के कारण विश्व की नवसाम्राज्यवादी ताकतें हिंदी को तोड़ने में जुटी हैं। वे भलीभांति जानती हैं कि यदि हिंदी इसी गति से बढ़ती रहेगी तो विश्व की बड़ी भाषाओं मसलन चीन की मंदारिन, अंग्रेजी, स्पेनिश और अरबी इत्यादि के समक्ष एक चुनौती बन जाएगी। कुछ समय पहले पंजाबी कनाडा की दूसरी राजभाषा बना दी गई है और हाल में संयुक्त अरब अमीरात ने हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया है। दूसरी ओर आज हिंदी मानव संसाधन की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम बन गई है। हिंदी चैनलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बाजार की स्पर्धा के कारण ही सही अंग्रेजी चैनलों का हिंदी में रूपांतरण हो रहा है। इस दौर में वेब-लिंक्स और गूगल सर्किट का बोलबाला है। इस समय हिंदी में भी एक लाख से अधिक ब्लॉगर सक्रिय हैं। अब सैकड़ों पत्र-पत्रिकाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। गूगल का स्वयं का सर्वेक्षण भी बताता है कि विगत तीन वर्षों में सोशल मीडिया पर हिंदी में आने वाली सामग्री में 94 प्रतिशत की दर से इजाफा हुआ है जबकि अंग्रेजी में केवल 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह इस बात का द्योतक है कि हिंदी वैश्वीकरण के संवहन में अपनी प्रभावी भूमिका अदा कर रही है। हिंदी की विकासमान शक्ति विश्व के समक्ष एक प्रभावी मानक बन रही है।

आखिर जो विषय साहित्य, समाज, भाषा विज्ञान और मनीषी चिंतकों का है उसे राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है। हिंदी का प्रश्न अभिनेताओं, नेताओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इस देश के जनसमुदाय ने उसे संपर्क भाषा के रूप में स्वतः स्वीकारा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब संविधान निर्माताओं ने देश की राजभाषा के रूप में हिंदी का सर्वसम्मति से चयन किया था तो उन्होंने स्वेच्छा से देशहित में बोलियों का बलिदान किया था, लेकिन अब कुछ ताकतें इस मोर्चे पर संघर्ष कराना चाहती हैं। याद रखें कि अपने संख्याबल के दम पर ही हिंदी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा हासिल कर सकती है। यदि भोजपुरी, राजस्थानी समेत हिंदी की किसी भी बोली को संविधान की आठवीं अनुसूची मे शामिल किया जाता है तो हिंदी बिखर जाएगी और यह सपना भी टूट जाएगा। इससे हिंद और हिंदी के सांस्कृतिक-भाषिक बिखराव की अंतहीन प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। हिंदी के संयुक्त परिवार की अनदेखी करने वाले आसन्न संकट को नहीं देख पा रहे। इस समय जो हिंदी का पक्ष नहीं लेगा उसे भावी पीढियां क्षमा नहीं करेंगी।

(लेखक मुंबई विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

## ऊर्जा

### नर में नारायण

लोग अपनी आस्थानुसार अपने आराध्य देवी-देवता के दर्शन के लिए जाते हैं और कल्याण की कामना करते हैं। जिस तादाद में धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की कतारें लगती हैं उससे तो यही समझ आता है कि वहां जाने से कुछ न कुछ तो जरूर मिलता है वरना कलियुगी इंसान के पास इन चीजों के लिए संसाधन और समय कहां है? बात भी ठीक है, तभी तो लोग मीलों लंबी लाइन में घंटों खड़े रहकर अपने इष्ट की झलक पाने के लिए हजारों मील दूर से तमाम तरह के इंतजामात करके वहां पहुंचते है। गौरतलब है कि लोग केवल उसी इष्ट के यहां ज्यादा हाजिरी लगाते है जहां से खाली हाथ लौटने की बात नहीं कही जाती है। यानी लोग वहीं जाना पसंद करते हैं जहां से मनोकामना पूरी होने के पूर्ण आसार बनने की संभावना हो। इससे स्पष्ट है कि जहां जाने से कुछ मिलता है लोग वहीं ज्यादा जाते हैं। दूसरी तरफ ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है जिसमें अपने बिल्कुल पास बने उसी इष्ट के दर्शन के लिए जाने में लोगों की उतनी रुचि नहीं होती है।

सांसारिक जीवन में इस तर्क को समाज के बड़े लोगों के यहां लगने वाली लाइन से जोड़कर देखा जा सकता है। बड़े राजनेता, अभिनेता, कलाकार, महात्मा या अन्य क्षेत्रों के बड़े लोगों के यहां लगने वाली लोगों की भीड़ को भी इसी नजरिये से देखा जा सकता है। मतलब यह कि इनके यहां भी अधिकांश लोग इसीलिए आते हैं कि या तो उन्हें वहां आने से कुछ मिलता है या मिलने की उम्मीद होती है। यह भी साफ है कि यह सिलसिला मुख्यतः तब तक ही चलता रहता है जब तक कि लोगों की मुराद पूरी होती रहती है। इसमे कोई खराबी भी नहीं है, क्योंकि समाज का प्रयोजन ही एक-दूसरे की मदद करना है।

बड़े लोगों को भी इससे खुश भी होना चाहिए कि उन्हें इस बहाने नर-नारायण की सेवा का मौका मिल रहा है। यहां आमजन से भी अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे भी अपने से बेहतर प्रतिभा की कद्र करें और उसको अपने इष्ट की तर्ज पर मन से उचित सम्मान दें और मानकर चलें कि अपने से बेहतर व्यक्ति में न केवल प्रतिभा अधिक है, बल्कि उस पर ईश्वर की कृपा भी अपेक्षाकृत ज्यादा है। यदि दोनों तरफ से ऐसी सोच बन सके तो प्रत्येक नर में नारायण देखने की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

डॉ. महेश भारद्वाज

# बिगड़ती आबोहवा के व्यापक दुष्प्रभाव

अरविंद जयतिलक

**जलवायु परिवर्तन से अनाज का उत्पादन घटेगा। इससे खाद्यान्न संकट के साथ ही विस्थापन की बड़ी समस्या भी उभर सकती है**

मूडी एनालिटिक्स द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था को जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान का हालिया आकलन बेहद चिंताजनक है। इसके नतीजे रेखांकित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ेगा। इसके मुताबिक यदि तापमान में चार डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है तो वर्ष 2048 तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर 2.45 फीसद के हिसाब से प्रतिकूल असर पड़ेगा। जिस तरह जलवायु परिवर्तन से तापमान में वृद्धि और वर्षा में उतार-चढ़ाव हो रहा है उससे मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हुई है और कृषि आय पर जोखिम बढ़ गया है।

संसद की एक की एक रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण देश में गेहूं और मक्के के उत्पादन में कमी आएगी। इसके मुताबिक यदि उचित कदम नहीं उठाए गए तो वर्ष 2050 तक गेहूं के उत्पादन में छह से 23 प्रतिशत और मक्के के उत्पादन में 18 प्रतिशत की कमी आएगी। अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा भी कम हो सकती है। इसी तरह यूरोपीय संघ के संयुक्त शोध केंद्र की एक रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर में अनाज का उत्पादन घटेगा। इससे खाद्यान्न संकट और गहरा हो सकता है और लोगों को अपना घर-बार छोड़ दूसरे इलाकों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में दुनिया भर में 77 करोड़ लोग भूख से पीड़ित थे जो 2016 में बढ़कर 81 करोड़ हो गए।

भारत के संदर्भ में कृषि की अनदेखी की बात करें तो आजादी के सात दशकों बाद भी विकास की तमाम योजनाओं के बावजूद किसानों की दशा में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। इससे किसानों का खेती से मोहभंग हो रहा है और वे अन्य कार्यों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इससे देश में किसानों की संख्या घट रही है जिसका सीधा प्रभाव अनाज उत्पादन पर पड़ रहा है। अनाज की बर्बादी भी चिंताजनक है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर साल उतना अन्न बर्बाद होता है, जितना ब्रिटेन उपभोग करता है। भारत में कुल उत्पादित भोज्य पदार्थ का तकरीबन 40 प्रतिशत बर्बाद हो जाता है। दुनिया के अन्य देशों की भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। बेहतर होगा कि अनाज की बर्बादी रोकने की दिशा में ठोस पहल की जानी चाहिए। अनाज के उत्पादन में कमी के लिए क्षेत्रवार विषमता का बढ़ना, प्राकृतिक बाधाओं से पार पाने में विफलता, भूजल का खतरनाक स्तर तक पहुंचना, जलवायु परिवर्तन आदि भी जिम्मेदार है। आश्चर्य यह कि इस दिशा में सुधार की कोई ठोस पहल नहीं हो रही है। अनाज उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है।

समय के साथ कार्बन उत्सर्जन की दर में भी वृद्धि हो रही है। अगर इसमें कमी नहीं आई तो वर्ष 2050 तक न केवल अनाज का उत्पादन कम होगा, बल्कि दुनिया भर में 15 करोड़ लोग प्रोटीन की कमी के भी शिकार होंगे। इस कारण 5.3 करोड़ भारतीय प्रोटीन की कमी से जूझेंगे। चूंकि खेती-बाड़ी का काम लगातार जटिल होता जा रहा है, लिहाजा आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि इसकी लागत को कम किया जा सके।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

## मेलबाक्स

### जनसंख्या वृद्धि पर लगाम जरूरी

देश-विदेश में गरीबी के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए और इससे निपटने के कुछ उपाय बताते हुए एनके सिंह ने 'गरीबी की पहचान का तरीका' शीर्षक लेख के तहत अपनी राय दी। इस मामले में हमें यह नहीं देखना है कि दुनिया के दूसरे देशों में गरीबी कितनी बढ़ी या घटी या फिर दूसरे देश इससे निपटने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। हमें यह देखना है कि अपने देश की सरकारों को कुंभकर्णी नींद से जगाना है ताकि वे गरीबी की पहचान उचित तौर-तरीके से कर देश पर लगे गरीबी के कलंक को मिटाने की कोशिश करे। गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को ही मिले। अगर देश में गरीबी की उचित पहचान होती तो आज देश में कोई गरीबी कारण भूखे पेट न सोता। देश में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो मोटी कमाई करते हैं, समृद्ध हैं, लेकिन फिर भी वे सरकार की तरफ से मिलने वाली उन योजनाओं का भी खूब लाभ लेते हैं, जो गरीबों के लिए होती है। अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली में जो गरीबों के लिए योजनाएं बनती हैं, वे भ्रष्टाचार के कारण देश के दूरदराज गांवों-शहरों तक पहुंचते- पहुंचते दम तोड़ जाती हैं। यहां यह कहना उचित होगा कि हमारे देश में गरीबी का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि भी है। हालांकि सरकार की कुछ नीतियां भी इसके लिए जिम्मेदार रही हैं। अब यह सिलसिला बदलना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

### समय की जरूरत है जल संरक्षण

जल सृष्टि का प्रमुख तत्व है तथा भारत को नदियों का देश कहा गया है। यहां छोटी-बड़ी करीब 100 नदियां बहती हैं। सिंचाई, पीने के पानी तथा अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिए पानी के अत्यधिक दोहन से भूमिगत जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। घटते जलस्तर ने भूवैज्ञानिकों तथा राजनीतिज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 60 करोड़ भारतीय पानी की समस्या से परेशान हैं। करीब 70 प्रतिशत घर पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हर साल 2 लाख लोगों की मौत साफ पानी नहीं मिलने की वजह से हो जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि हालत में सुधार नहीं हुआ तो आने दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विषय की गंभीरता को देखते हुए जल संरक्षण के लिए अलग से जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर बनाया गया। प्रधानमंत्री का यह प्रयास सराहनीय है। आने वाले समय में भारत अवश्य ही जल संकट से उबरेगा। हालांकि मंत्रालय अपना कार्य करेगा, परंतु बिना जन सहभागिता के जल संरक्षण संभव नहीं है। जल संरक्षण के लिए आम जनता को भी आगे आना पड़ेगा। हमें गांव-गांव में जल रक्षक बनाने पड़ेंगे। पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए जन जागरण अभियान चलाने की आवश्यकता है। जल सरंक्षण के जितने भी छोटे बड़े उपाय हों, किए जाने चाहिए। वर्षा के पानी के संरक्षण के लिए घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाना चाहिए।

thakurkk999@gmail.com

### अस्पताल की सराहनीय मुहिम

लखनऊ के राममनोहर लोहिया अस्पताल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए नई पहल की है। वह अपने यहां भर्ती मरीजों के स्वस्थ होने पर उनसे अपने घर जाकर एक पौधा लगाने की शपथ लेगा जो मरीजों के डिस्चार्ज होने के समय देना होगा। यह मानवीय दृष्टिकोण से भी बहुत ही फायदेमंद है, जिसका दूरगामी परिणाम मिलेगा। जाहिर सी बात है कि अगर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगेंगे तो उतनी ही पृथ्वी पर हरिया